# राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आतंकवाद : एक चुनौती
## [ समस्या एवं समाधान ]

शोधपत्र-राजनीति विज्ञान

* श्रीमती रीमा रानी दास

भारत की लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था का आधार राष्ट्र की प्रगति एवं राष्ट्र में रहने वाले लोगों की उ्न्नति है। राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता की रक्षा करने एवं अलगाव वादी ताकतो से देश की समृद्धि की रक्षा करना ही राष्ट्र का प्रमुख दायित्व हैं। राजनीतिक स्थिरता ही सामाजिक व्यवस्था की कुंजी है। किन्तु परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन भी अवश्यक है। किसी भी परिवर्तन के इस दृष्टिकोण से देखा जाये कि इससे देश की एकता में वृद्धि होगी या देश खण्डित होगा। राजनीति व्यवस्था में सरकार की अहम् भूमिका है। एक सशक्त सरकार का मुख्य दायित्व हे, आंतरिक भांति व्यवस्था बनायें रखना एवं वाह्य आक्रमणों से राष्ट्र की सुरक्षा के साथ ही साथ अन्त्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्वेच्छा से सम्बन्धों का विकास करना 'राष्ट्र की सुरक्षा ही सर्वोपरि है, इस उद्देश्य को धयान में रखकर सरकार द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। सरकार के सक्षम आंतरिक क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं में प्रमुख समस्या नक्सलवाद से निपटने की है, जो कुछ राज्यों तक विस्तृत है वाह्य एवं आंतरिक क्षेत्र में एक प्रमुख समस्या है, आतंकवाद जो विश्व की प्रमुख समस्या बन चुकी हैं।

**आतंकवाद** :– पिछली सदी तक आतंकवाद का रूप रक्तपूर्ण एवं संवैधानिक था जो कामगार वर्ग के साम्राजय की स्थापना की अनिवार्य शर्त थी, इस आतंकवाद का स्वरूप कालदाता के रूप में फलता फूलता था। आतंकवाद क्या हैं, आतंकवाद का तात्पर्य हैं,–

''आतंकवाद मुख्यतया कुछ व्यक्तियों के एक समूह लोगो द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति एवं सुविधाओं के खिलाफ किया गया अपराधिक कार्य हैं'' आतंकवाद का उद्देश्य है हिंसक कार्यवाही द्वारा समाज से अपनी मांगे मनवाना। दूसरे शब्दों में आतंकवादी वह है जो अपनी मांगे मनवाले के लिये चरम हिंसा का प्रयोग करके व्यक्ति विशेष समाज या किसी सरकार पर दबाव डाले अर्थात आतंकवाद का तात्पर्य है, अपनी मांगे मनवाने के लिये बल प्रयोग।

आंतकवाद की कार्यप्रणाली :– आतंकवादी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये विभिन्न तरीकों एवं प्रणालियां का उपयोग करता है, जो इस प्रकार से हैः–

(1) विमानो का अपहरण। (2) राजनयिक व प्रमुख हस्तियों का अपहरण। (3) सार्वजनिक नेताओं की हत्या।

इनकी गतिविधियॉ इन क्षेत्रों तक फैल गयी। बीसवें दशक में 'आतंकवाद' से कोई खतरा नहीं था सातवे दशक में इसे 'शहरी आतंकवाद' का नाम दिया गया। मिजो नेशनल फ्रण्ट की आंतकवादी गतिविधियॉ 'गुरिल्ला पद्धति '' पर आधारित थी। उन्हें प्रशिक्षण व शस्त्र सामग्री पडो़सी देश चीन व बर्मा से प्राप्त होता था। भारत सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिये ''समझौता वार्ता'' का प्रयत्न किया। 1985 में के मध्य में लालडेंगा ने मिजोरम राष्ट्रीय मोर्चे के लगभग 600 कट्टर विद्रोहियों के साथ हथियार सहित समर्पण किया। राजीव लालडेंगा समझौते द्वारा समस्या का समाधान हुआ। उत्तर पूर्वी राज्य के प्रति भारत सराकार ने अधिक सजगता का परिचय दिया।

पंजाबः– सिक्ख देश की मांग भारत की स्वतंत्रता से पूर्व भी। खालसा पंथ का कहना था कि सिक्खों को धोखाध ड़ी से भारतीय गण्तंत्र में सम्मिलित होन के लिये विवश किया। 19880 –1992 के समय सिक्खों द्वारा खालिस्तान की मांग अर्थात एक स्वतंत्र सिक्ख राज्य पंजाब के रूप में उन्हें मिले । इसका समर्थन करने वाले कुछ मुठ्ठी भर उग्र तत्व थे। 1983 के आसपास पंजाब आतंकवाद का अड्डा बन गया, जब भिंडरावाले के नेतृत्व में सिंखों के उग्रवादी संगठन ''इंडिया सिंक्ख स्टूडेन्टस फेडरेशन'' (AISSF) और दशमेश रेजीमेंट तथा बब्बर खालसा के सदस्यों ने आतंकवादी गतिविधियों का संचालन किया, जिसमें मोटर साइकिल पर सवार होकर हत्याये करना बम विस्फोट करना, एक विशेष सम्प्रदाय के लोगों की हत्यायें करना आदि।

खालिस्तान आंदोलन जो आतंकवाद का रूप बन गया था, उसे विदेशों में रहने वाले सिक्खों का समर्थन प्राप्त का यह आंदोलन अमरीका में बसे हुऐ गंगासिंह ढिल्लो और इंग्लैंड में बसे रणजीत सिंह द्वारा चलाया जा रहा था, इनके

*सहायक प्राध्यापक, राजनीतिक विज्ञान, शा. डी. के महाविद्यालय बलौदा बाजार, रायपुर

संगठन सभी बड़े शहरों मे थें 1981 में सिक्ख नौजवान द्वारा 'इंडियन एयरलाइन्स' के विमान का अपहरण करना और लाहौर ले जाना। 1984 में जब आतंकवाद अपने शीर्ष पर पहूंचा , तब श्रीमती इंदिरा गॉधी ने ''ऑपरेशन ब्लूस्थर संगठित कर अमृतसर के स्वर्णमंदिर पर सैनिक कार्यवाही कर, आतंकवादयों को गिरफ्तार किया, इस कार्यवाही के बाद सिक्ख आतंकवादी गुटों की सूची में प्रधानमंत्री गांधी का नाम सम्मिलित हुआ 31 अक्टुबर 1984 को श्रीमती गांधी की हत्या हुई, एवं दिल्ली में निर्दोश सिक्ख मारे गये। 1985 से आतंकवाद का घृणित रूप 'ट्रास्जिस्टर बम' के रूप में आया, कई नेताओं की हत्या इन बमों के द्वारा हुई। तब प्रधानमंत्री (राजीव गांधी) ने अनुभव किया कि इस समस्या का हल कठोरता नहीं है, इस सम्बन्ध 24 जुलाई 1985 को राजीव गांधी व लोगोंवाल समझौता हुआ आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ बल्कि इसके विपरीत लोगोंवाल की हत्या 20 अगस्त 1985 को आतंकवादियो ने की, आतंकवादियों 1985 को पंजाब के मुख्यमंत्री वैअंत सिंह की भी हत्या कर दी। आतंकवादियों, द्वारा की जा रही निरतंर गतिविधियों से पंजाब का व्यापार एवं उद्योग धन्धें ठप पड़ गये। इसीकाल में इस आतंकवाद को सिख आतंकवाद की संज्ञा दी गई जो सही नही था, इस कारण उसे उग्रवाद का नाम दिया गया। 1992 में पंजाब में चुनाव के राजनीति व्यवस्था कायम हुई सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि वे उग्रवादियों के अलगाव वादी खेल को सफल नही होने देगें। कुछ समय वाद यह प्रवृति फिर उभरी, किन्तु वर्तमान समय में पंजाब में शांति व्यवस्था कायम है।

**जम्मू–काश्मीर**– जम्मू काश्मीर में 1987 से ही आतंकवाद की स्थिति बनी इस क्षेत्र में तीन आतंकवादी संगठन सकिय थे जैसे 'जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रण्ट 'काश्मीर लिबरेशन आर्मी, हिजबुल मुजाहिद्दीन एवं जमाते उलमा आदि। इनका उद्देश्य जम्मू काश्मीर को स्वतंत्र करा के स्वतंत्र राज्य का दर्जा देना। जबकि कुछ का उद्देश्य जम्मू काश्मीर का पाकिस्तान का विलय ' इन आतंकवादियों ने लंदन मं भारतीय राजदूत म्हात्रे का अपहरण कर उनकी हत्या करदी। इन आंतकवारियों का मुख्य उद्देश्य आतंक फैलाना इसकेक लिये वे विभिन्न तरीके अपनाते है जैसे–लूटमार, अपहरण, विस्फोट और हत्या आदि। इसी ध्येय की प्राप्ति के लिय उन्होनें 1989 में गृहमंत्री (सईद) की पुत्री का अपहरण किया अन्य अधिकारियों का अपहरण कर उनकी हत्या की, जिसमें विदेशी पर्यटक भी सम्मिलित थे। 1990में आतंकवाद काश्मीर तक सीमित न रहकर जम्मू तक फैल गया ।

1988 में सार्क शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पाकिस्तान पर अरोप लगाया कि पाकिस्तान द्वारा आतकवादियों को भौतिक और नैतिक समर्थन दिया जा रहा है। पाकिस्तान भारत के आंतरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा था, काश्मीर घाटी में विघटनकारी आतकंवादियों को हर प्रकार सहयता व प्रशिक्षण दे रहा था। धर्म के नाम पर जिहाद छेड़ने हुये आतंकवादियों को प्रशिक्षण, देना शस्त्र देना एवं नैतिक समर्थन देना निरतंर जारी था। काश्मीर घाटी के हजरत वल दरगाह पर आतंकवादियों का प्रवेश पाकिस्तान के प्रथम पर था। भारत सरकार के विरोध व कार्यवाही कारण 16 अक्टुबर 1993 को आतंकवादियों ने आत्म समर्पण किया। 1995 से भारत बार बार कहता आ रहा है कि काश्मीर में उपद्रव एवं आतंकवादियों

गतिविधियॅा काश्मीर द्वारा प्ररित नहीं , बल्कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की प्रेरणा से इन्हे प्रेशिक्षण (अन्तर्राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसी ) आई. एस. आई. द्वारा दिया जा रहा हैं। इनके विभिन्न प्रशिक्षण शिविर चलाये जा रहे है। इस सम्बंध में लश्कर–ए–तयबा ने मुजफ्फराबाद में प्रेस सम्मेलन में स्वीकार किया उनके संगठन ने काश्मीर में शंघर्ष में सम्मिलित होने के लिये लोदन को आमंत्रित किया है 1989 में कारगिल युद्ध के समय भूतपूर्व सेनाअध्यक्ष राय चौधरी ने कहा कि ''भारत के खिलाफ पाक (जिहाद) धर्मयुद्ध की ध्यान में रखते हुये हमें लम्बी अवधि की राष्ट्रीय सुरक्षा योजना बनानी होगी।''

**असम उत्तर पूर्वी राज्यों गोरखालैण्ड और झारखण्ड आदि क्षेत्रों में आतंकवाद** :–असम के 1947 से ही पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र (पूर्वी बंगाल) से व्यक्तियों का आना शुरू हुआ जिनकी संख्या कभी कम, कभी अधिक थी, 1970 के बाद एवं 1971 में स्वंत्रत बंगला देश की स्थापना के बाद असम में आनेवाले घुसपैठियों की संख्या लारगें में पहुॅच गई। ये घुसपैठियै, अवैध रीति से असम में रहने से असम वासियों की सामाजिक, आर्थिक जीवन, अपनी जातीय एवं सांस्कृतिक पहचान के लिये संकट उत्पन्न करने लगे। तब असम सरकार ने विदेशियों असम आगमन पर रोक लगा दीं। एवं विदेशियों के बसने पर भी इस व्यवस्था को I nner line Permit' का नाम दिया गया' असम में 1989 के अंतिम महीनों में ही एक उग्रवादी संगठन 'उल्फा' उठ खड़ा हुआ। इस संगठन का उद्देश्य असम अलग सम्प्रभु राज्य बनाना था। इनके तरीके थेः हिंसक आंदोलन जबरन वसूली अपहरण हत्या आदि 1991 के प्रारम्भ में आतंकवादी गतिविधियों में अत्यंत वृद्धि हुई भारत सरकार ने असम को ''अशांत क्षेत्र '' घोषित कर दिया ।

और उल्फा के विरूद्ध 'ऑपरेशन बजरंग' के नाम से सैनिक कार्यवाही की गई। उल्फा आतंकवादियों को नियंत्रित करने के लिये सिंतम्बर 1991 मे एक अन्य सैनिक कार्यवाही की गई। उल्फा आतंकवादियों को नियंत्रित करने के लिये सितम्बर 1991 में एक अन्य सैनिक कार्यवाही ''ऑपरेशन राइनो' के नाम से की गई। इस अभियान को जन सहयोग प्राप्त हुआ। 1 वर्ष की अवधि में इस आंदोलन ने सफलता प्राप्त किया।

सन् 1990 के काल में असम में हुई हिंसा में की 141 घटनायें हुई जिसमें 107 लोगों मारे गये। जिसकी जवाबदेहता उल्फा पर थी। वोडो उग्रवादी आंदोलन भी असम में शुरू हुआ, जिसका नाम वोडो सुरक्षा बल था, जिसका परिवर्तित नाम वोडो सुरक्षा बल था, जिसका परिवर्तित ना 'नेशनल डमोक्रेटिक फ्रण्ट ऑफ बोडोलैण्ड' रखा गया। इनके द्वारा 174 हिंसक गतिविधियॉ की गई, जिसमें 201 व्यक्ति मारे गये 1995 में हुई हत्या के मुकाबले 39% है अधिक थी। 1996 के उत्तरार्द्ध में वोडो लिवरेशन टाइर्गस फोर्स ने पुनः शस्त्र उठा लिया। जिससे जन एवं धन की हानि हुई। त्रिपुरा राज्य में इस समय 15 जनजाति उग्रवादी संगठन है। जिसमें 'नेशनल लिवरेशन फ्रण्ट आफ त्रिपुरा , एवं त्रिपुरा टाईर्गस फोर्स से अधिक संक्रिय है।

असम में होन वाली गतिविधियों में 1990 से 2002 तक उतार चढ़ाव आते रहे । यह पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहित हैं बंगलादेश एवं म्यांमार (बर्मा) में भी यही स्थिति थीं। विगत तीन वर्शो से उत्तर पूर्वी भारत के प्रति सरकार ने अधिक सजगता का परिचय दिया। वर्तमान समय में असम के शिलांग में गारो जनजाति का उग्रवादी संगठन हिंसक कार्यवाही कर रहा हैं। भारत के प्रमुख राज्यों पर निरतंर आतंकवादी आक्रमण 1990 से 26 नवम्बर 2008 तक हुई हुये जिनका विवरण निम्नानुसार है। आतंकवादी विवरणः–

भारत मे हुये आतंवादियों आक्रमण से विश्व के सामने हमारे देश लचर सुरक्षा व्यवस्था अजागर होती है। अभी तक यह माना जाता रहा है। कि भारत की वाह्य सुरक्षा खतरें में है , जैसे भारत तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है ओर चौकी ओर हिमालय पर्वत है भारत की आतंरिक व्यवस्था की आंतकी धटनाओं से छिन्न भिन्न हो रही हैं वर्तमान समय में होने वाली आतंकी आक्रमण का स्वरूप आज से 12 वर्ष पूर्व होने वाली आतंकी अक्रमण से पृथ्क है। वर्तमान समय में आतंकवाद का रूप अत्यंत विकराल है। निर्द्रोश व्यक्तियों की हत्या करना आतंकियां के लिये अत्यंत साधारण सी बात हैं जैसे कि 2001 में संसद पर आक्रमण , 2002 में अक्षर धाम मंदिर पर आक्रमण आदि। 2005 में रामलला मंदिर पर निशाना लगाना। आतंकवादियों ने अपने आक्रमण का क्षेत्र भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र को बनाया चार आक्रमणों के द्वारा आतंकवादियों ने भरत की आतंरिक व्यवरूथा को छिन्न–भिन्न किया। यह। आक्रमण योजना बद्ध रीति से अभिप्रेषित आतंकवादियों संगठन द्वारा किया इस गतिविधियों में संलिप्त किया प्रशिक्षित कमांडों को।

मोलेगांव बमकांड जिसने आतंकवाद को नयी रूप दिया जिसे हिन्दू आतंकवाद की संज्ञा दी गई, आतंकवाद के कई नाम है इस्लामिक देश अफगानिस्तान – पाकिस्तान समर्थित, इस्लामी आतंकवादी , इडियन मुजाहिद्दीन जैसे आतंकी संगठन द्वारा चलायें आतंकी गतिविधियों को मुस्लिम आतंकवाद या देशी आतंकवाद का नाम दिया गया। प्रसिद्ध मालेगॉव बम कांड जिनके संचालक साध्वी प्रज्ञासिंह एवं कर्नल पुरोहित है, जिनका संगठन अभिनव भारत '। इन धमाकों के लिये कर्नल पुरोहित ने 2007 में समझौता एक्सप्रेस से 60 किं. ग्रा. का आर डी एक्स चोरी किया उनके द्वारा की गई हिंसक कार्यवाही में 68 लोग मारे गये।

भारत की समुद्री तटों की सुरक्षा की जवाबदेयता प्रतिरक्षा मंत्रालय की है गुजरात सरकार अपनी सम्रुदी तटो की सुरक्षा के लिये चिन्तित रहता है। जब 1993 में पाकिस्तान से नावों द्वारा आर. डी. एक्स लाया गया तब समुद्री रास्तो से आतंकी आक्रमण की शंका की गई। इसके अतिरिक्त जब गुजरात के समुद्र तट से मुम्बई जाने के लिये व्यापारी नौका ' कुवेर ' का अपहरण किया गया तो गुजरात सरकार इस सम्बन्ध में मुम्बई सरकार कोआगाह किया, किन्तु सरकार एवं सुरक्षा बलो ने इस ओर ध्यान नही दिया। 26 नबम्बर 2008 को मुम्बई पर हुआ आतंकी आक्रमण समुद्री मार्ग से हुआ ये आतंकी रबर की नौका से मुम्बई के समुद्री तट पर आये आर्थिक मंदी के इस युग में भारत व अमेरिका के परमाणु करार का रोकने के लिये एवं भारत की आर्थिक स्थिति निर्बल करने के लिये तथा भारत की साख को क्षति पहुॅचाने के लिये किया गया। मुम्बई के प्रसिद्ध ताज एवं ओंबराय होटल, जिसमें विदेशी पर्यटको की अधिक संख्या का हेना, मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज बड़े कारोबारी समूहों के मुख्यालय,मेलि लिंच मार्गन स्टैनले और एच.एस.बी. होलिडंग्स जैसी बड़ी कम्पनियां जो आथ्रिक व्यवस्था का आधार है, आतंकी आक्रमण हुआ जिसमें निर्दोश लोगो की जानें गई एवं 4000 करोड़ रूपयें की हानि हुईं इस आतंकी आक्रमण को आर्थिक आतकवाद की संज्ञा दी गई। विभिन्न आतंकवादियों संगठन, जैश .ए. मोहम्मद, लश्कर–ए. तैयवा, हरकत–अल–जिहाद अल इस्लामी (हूजी), अलकायदा, हिज्बुल मुजाहिद्दिन इंडियन

मुजाहिद्दीन आदि। भारत सरकार ने बाह्य एवं आतंरिक सुरक्षा के लिये विभिन्न संगठन तैयार किये हैं उदाहरण के लिये :– रॉ, आई बी, एन टी आर आई. राज्यों के गुप्तचर ब्यूरो आदि जो समूह की सुरक्षा हेतु कार्यवाही करने हे आतंकी आक्रमणों को मुकाबला भी वे बडी तत्परता से करते है । जैसे मुम्बई की आतंकी आक्रमणों का मुकाबला करते हुये कई सुरक्षा सैनिको ने अपने प्राण निछावर कियें। किन्तु फिर हमारी सुरक्षा व्यवस्था में खामियॅा है कॉरगिल के समय अपने शौर्य का प्रदर्शन का करने वाले ललाकृश्ण पाल ने कहा था कि ''अत्प्रत्यक्ष युद्ध मे पराजय के बाद उसे फिर से द्योड़ो और युद्ध उन्माद फैलाकर स्थिति अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने के उद्देश्य से कारगिल में जिहादी अतंकियों को पाकिस्तानी सेना सहयोग कर रही है। की संकेत दिया '' मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने 5 सितम्बर 2006 को नई दिल्ली में कहा था कि .........'' देश के भीतर आतंकवादी संगठनों की बढ़ती हुई गतिविध्यिों पर प्रतिबन्द्ध लगाना है'' भारत सरकार ने आतंकवाद को एक चुनौती माना प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2008 में कहा कि '' बैगलौर , अहमदाबाद, जयपुर और देश के अन्य भागों मे हुये आंतकी आक्रमण एक निन्दनीय की कार्य है। '' भारतीय समुद्री तटों की सुरक्षा अत्यंत दुरूह कार्य हे जिसकी जवाबदेयता प्रतिरक्षा मंत्रालय पर है, इस हेतु मंत्रालय मे नोसेना एवं कोस्टगार्ड की व्यवस्था की हैं समय –समय पर समुद्री तटों की सुरक्षा हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया जाता है, यह नौकर शाही के गलियारे में खे जाता है। यह व्यवस्था व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित नही हो पाती है जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था की कमियॉ उजागर होती है।

सुझाव :– भारत में आतंकवाद की प्रवृत्ति को रोकने के लिये आतंकवाद विरोधी कानून ''पोटा'' से भी अधिक कठोर कानून लोने की आवश्यकता हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि ''अधिक मर्यादित केन्द्रीय जॉच एजेन्सी की आवश्यकता है'' जिसके द्वारा अन्तराज्यीय एवं अंतिरक सुरक्षा वाल मामले देखे जाये । गृह मंत्रालय इस प्रारूप पर कार्य कर रहा है। एक राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकरण की कल्पना की गई है। जिसका कार्य देश भर में आतंकवाद से जुड़े अपराधों के प्रकार की जॉ.च करना , उसकी निगरानी करना, यह अध्यक्ष सहित पॉच सदस्यीय होगा। जिसके द्वारा अभियुक्तो पर मुकदमा चलाया जायेगा। प्रत्येक राज्य मे एक सुरक्षा आयुक्त नियुक्त किया जो वरिश्ट आइ. पी. एस. अधिकारी होगा। कुछ लोगो का कहना है कि आतंकवाद से जुंड़े अपराधों को राज्य सूची से हटाकर संघीय या समवर्ती सूची पर लाने के पक्षधर है कुछ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विरोध में कठोर कानून लाये जा सकते है। विशेषज्ञो का मानना है कि कानूनो में संसोधन कर रहम या दया के प्रावधानो को हटाने का सुझाव दिया हैं, जैसे कि आतंकवादी अफजल गुरू की फॉसी की सजा को टालना । या साधवी प्रज्ञासिंह को जेल में डालना और भाजपा द्वारा उनको पक्ष लेना ।

**मूल्यांकन** :– आतंकवाद विश्व की प्रमुख समस्या बन चुकी है,, विश्व के प्रायः सभी देशों के आंतकी आक्रमण हुये किन्तु भारत में सबसे अधिक आतंकी हमले हुये इस तथ्य को स्पष्ट किया अमेरिका का भूतपूर्व विदेश सचिव ने। इसमें अलावा 2009 जुलाई में हुये जी 8– देशों के सम्मेलन में भी इसे स्वीकार किया गया। भारत में होने वाली आतंकवादी घटनायें या आक्रमण पाक–एवं अफगानिस्तान समर्पित है। किन्तु भारत में होने वाली आंतकी आक्रमण बाह्य देशों की सहायता से नहीं,, बल्कि देश के आंतरिक क्षेत्र से पनप रहा है। वास्तव में आतंकवाद को प्रोत्साहित करने का श्रेय जाता है उन लोगों को देश की मुख्य धारा से न जुड़कर अपने पृथक अस्तित्व के लिये तैयार रहते है और सरकार द्वारा दी गयी सुविधा से संतुश्ट नही होते है, अपनी स्वार्थ परता के लिये आतंकवादी गुट तैयार करना या आतंकी संगठन में सम्मिलित होना या उन्हें सहायता करना। जैसे कि प्रतिलन्धित सिमी, द्वारा समर्पित इंडियन मुजाहिद्दीन अभिनवभारत देश के अंदर पनपते हुये आतंकवादी संगठन सिद्ध करते है कि घर का भेदी लंका ढाय' प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 15 जलाई 2009 को गुटनिरपेक्ष देशो के सम्मेलन में मिस्त्र में कहा है कि आंतकी ढॉचों को खतम करने एवं आतंकियों को ही नही बल्कि उसका समर्थन करने वालो को सजा देने के लिये ठोस प्रयास किये जाने चाहिये

## सन्दर्भ ग्रन्थ

(1) इंडिया टुडे (28) 7 जनवरी 2008 पृष्ठ 28 (2) भारतीय राजनीति एवं शासन डॉ वी.एल.फड़िया पृष्ठ 750, 751,पृष्ठ 341,342, पृष्ठ 287 पृष्ठ 752, (3) राजनीति विज्ञान डा. पुखराज जैन, पृष्ठ 195 (4) भारतीय राजनीति एवं शासन जैन एवं फड़िया पृष्ठ 752, पृष्ठ 753, (5) प्रमुख देशों की विदेश नीतियॉ बी.एच. जैन पृष्ठ 298,पृष्ठ 300, पृष्ठ320,321,325, (6) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति बी. एल. फड़िया पृष्ठ 752,234, (7) इंडिया टुडे 17 दिसम्बर 2008 पृष्ठ 39, पृष्ठ17 (8) कारगिल वी.पी. मलिक पृष्ठ 101, 340, (9) अमृत संदेश 16 जुलाई 2009 पृष्ठ 01 (10) इंडिया टुडे 13 अगस्त 2008 पृष्ठ 25 (11) इंडिया टुडे 15 अक्टुबर 2008 पृष्ठ 33